



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2017/ज्येष्ठ 26, 1939

No. 495]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2017/JYAISTHA 26, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2017

सं. 30/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 597(अ).**—जहांकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अमीरात (एतश्मिन पश्चात् जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से मामूली मोटाई के अर्थात् 4 मिमी. से 12 मिमी. तक के (दोनों सीमाएं शामिल हैं) निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास, जिनकी मोटाई BIS 14900:2000, (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत माल कहा गया है) के अनुसार है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/25/2012-DGAD, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014, जिसे दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अपने अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि घरेलू उद्योग को नुकसान न होने पाए इसके लिए विषयगत देश से आयात किए जाने वाले सभी विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना चाहिए;

और जहांकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 48/2014-सीमा शुल्क, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014, जिसे सा.का.नि. 885(अ), दिनांक

11 दिसम्बर, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहांकि, मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एतश्मिन पश्चात् जिसे "न्यू शिपर" से संदर्भित किया गया है) ने अपने द्वारा निर्यात किए गए माल के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ (अभिज्ञान, आकलन और पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क का संकलन और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 22 के अंतर्गत समीक्षा का अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर अधिसूचना सं. 15/16/2015-DGAD, दिनांक 23 सितम्बर, 2015, जिसे 23 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत न्यू शिपर के द्वारा किए जाने वाले विषयगत माल के सभी निर्यात के अनंतिम आकलन, जब इनका आयात भारत में हो, की तब तक अनंतिम आकलन किए जाने की सिफारिश की है, जब तक कि यह समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता;

और जहां कि, उक्त नियमावली के नियम 22 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 53/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 825(अ), दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा यह आदेश दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के परिणाम के आने तक जब मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (निर्यातक) के द्वारा निर्यात किया गया हो तो निर्यातित माल अनंतिम आकलन के तहत ही रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है;

जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/16/2015-डीजीएडी जिसे 23 सितंबर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू के मामले में अधिसूचना सं. 15/16/2015-डीजीएडी, जिसे 10 अप्रैल 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया था, हमें अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान के द्वारा उत्पादित, निर्यातित 'क्लियर फ्लोट ग्लास, जिसकी नोमिनल थिक्नेस 4 मिमी से 12 मिमी तक हो, यह नोमिनल थिक्नेस बीआईएस 14900;2000 के अनुसार,' जोकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 के अन्तर्गत आते हैं, के आयात पर 23.54 अमेरिकी डॉलर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए।

अतः सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20, 22 तथा 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् एतद्द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन करती है:—

(क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 48/2014 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 11 दिसंबर 2014, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) दिनांक 11 दिसंबर 2014 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 885(अ), दिनांक 11 दिसंबर 2014 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नानुसार संशोधन किए जाएं:

(i) उक्त अधिसूचना की तालिका में:—

(क) क्रम सं 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को अंतस्थापित किया जाए, नामतः—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
“10क	7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020	मामूली मोटाई के अर्थात् 4 मिमी. से 12 मिमी. तक के (दोनों सीमाएं शामिल हैं) निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास, जिनकी मोटाई BIS 14900:2000 के अनुसार हो	पाकिस्तान	पाकिस्तान	मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड	23.54	MT	USD”;

(ख) क्रम संख में कॉलम (6) तथा (7) में, प्रविष्टियों में शब्द, अक्षर तथा अंक ‘क्रम सं 10’ के पश्चात् शब्द, अक्षर तथा अंक ‘तथा क्रम संख्या 10 क’ को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) विषयगत माल के सभी आयात, जोकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 53/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के अनुसरण में अनंतिम निर्धारण के अधीन है, प्रतिपादन शुल्क के भुगतान पर अंतिम निर्धारण के अधीन होंगे, जैसा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं 48/2014-सीमाशुल्क, दिनांक 11 दिसंबर 2014 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 885(अ), दिनांक 11 दिसंबर 2014 के तहत प्रकाशित की सारणी में क्रम सं० 10 क तथा 11 में उल्लिखित हैं।

(ग) अधिसूचना सा.का.नि. 825(अ), दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं 53/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक अक्टूबर, 2015 को ऐसे निस्तारण से पूर्व की गई या लोप की जाने वाली संबंधित बातों को छोड़कर रद्द कर दिया जाएगा।

2 तथा जबकि, अधिसूचना सं० 15/6/2015 डीजीएडी, दिनांक 10 अप्रैल, 2017, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I खंड 1, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित किया गया है को रिट याचिका सं 2017 की 12950 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी तथा उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.05.2017 के आदेश के माध्यम से इस मामले को ‘मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए, दिनांक 09.06.2017 तक यथास्थिति का अनंतिम आदेश दिया जाए’ रोक रखा है।

3 अब इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश को देखते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त रिचयाचिका सं 2017 की 12950 में अंतिम आदेश आने तक प्रास्थगित रहेगी।

[फा. सं. 354/ 46/2014-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Expenditure)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2017

**No. 30/2017-Customs (ADD)**

**G.S.R. 597(E).**—Whereas, in the matter of import of Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12 mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900:2000, (hereinafter referred to as the subject goods), falling under headings 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 14/25/2012-DGAD, dated the 10th October, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th October, 2014, had recommended imposition of anti-dumping duty on all imports of subject goods from the subject countries in order to remove the injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2014-Customs, dated the 11<sup>th</sup> December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 11<sup>th</sup> December, 2014, *vide* number G.S.R. 885(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2014;

And whereas, M/s Tariq Glass Industries Ltd (hereinafter referred to as the “new shipper”) had requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* the new shipper notification No. 15/16/2015-DGAD, dated the 23<sup>rd</sup> September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23<sup>rd</sup> September, 2015, had recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the new shipper when imported into India, till the completion of the review by it;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the said rules, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2015-Customs, dated the 30<sup>th</sup> October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 825(E), dated the 30<sup>th</sup> October, 2015 had ordered that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when exported by, M/s Tariq Glass Industries Ltd. (exporter), shall be subjected to provisional assessment till the review is completed;

And whereas, the designated authority in the matter of new shipper review initiated *vide* notification No. 15/16/2015-DGAD, dated the 23<sup>rd</sup> September, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated 23<sup>rd</sup> September, 2015 in its final findings *vide* notification No. 15/16/2015-DGAD, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10<sup>th</sup> April, 2017 has recommended the imposition of anti-dumping duty of United States Dollar 23.54 per Metric Tonn on imports of “Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900:2000” falling under Chapter 70 of the Custom Tariff Act, 1975 produced and exported by M/s Tariq Glass Industries Ltd, Pakistan.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18, 20, 22 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government, hereby makes the following changes:

(a) the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 48/2014-Customs (ADD) , dated the 11<sup>th</sup> December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 11<sup>th</sup> December, 2014, *vide* number G.S.R. 885(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2014, shall be amended as under:

(i) in the said notification, in the Table,—

(A) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
“10A	7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020	Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900:2000	Pakistan	Pakistan	M/s Tariq Glass Industries Ltd	M/s Tariq Glass Industries Ltd	23.54	MT	USD”;

(B) in serial number 11, in column (6) and (7), in the entries, after the word, letters and figures “Sl. No. 10”, the word, letters and figures “and Sl. No. 10A” shall be inserted:

(b) all imports of the subject goods which have been subjected to provisional assessment pursuant to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2015-Customs, dated the 30<sup>th</sup> October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 825(E), dated the 30<sup>th</sup> October 2015 shall be subjected to final assessment on the payment of anti-dumping duty, as mentioned at Serial Numbers 10 A and 11 in the Table to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2014-Customs, dated the 11<sup>th</sup> December, 2014, published, *vide* number G.S.R. 885(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2014;

(c) the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2015-Customs (ADD), dated the 30<sup>th</sup> October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 825(E), dated the 30<sup>th</sup> October, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, shall be rescinded.

2. And whereas, the said final findings notification No. 15/16/2015-DGAD, dated the 10<sup>th</sup> April, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10<sup>th</sup> April, 2017, was challenged in the Hon’ble Madras High Court in Writ Petition No. 12950 of 2017 and the Hon’ble High Court *vide* its order dated the 25<sup>th</sup> May, 2017 has held that “*Considering the facts and circumstances of the case, there shall be an interim order of status quo till 09.06.2017.*” ;

3. Now therefore, in view of the aforesaid order of the Madras High Court the present notification shall remain in abeyance, subject to the final order of the Hon’ble Madras High Court in the aforesaid Writ Petition No. 12950 of 2017.

[F. No. 354/46/2014-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.